मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 67
02 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना

67 # श्री नीरज डांगी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा हाल ही में औद्योगिक स्मार्ट शहरों (आईएससी) की स्थापना का उद्देश्य क्या है और इसमें शामिल राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) औद्योगिक स्मार्ट शहरों (आईएससी) में निवेश हेतु किन-किन क्षेत्रों में निवेश की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक स्मार्ट शहरों (आईएससी) को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्र के नागरिकों के लाभ हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) औद्योगिक स्मार्ट शहरों (आईएससी) के तहत आवंटित की गई और व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

'औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना' के संबंध में 02.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 67* (7 वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एनआईसीडीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर/क्लस्टर बनाना है। इन शहरों के विकास का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास "आत्मनिर्भर भारत", अवसंरचना विकास, निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार, स्थिरता और हरित कार्यों, तकनीकी नवाचार, शहरीकरण और स्मार्ट शासन, क्षेत्रीय आर्थिक विकास और कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। भारत सरकार द्वारा 28.08.2024 को एनआईसीडीपी के तहत 12 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) एनआईसीडीपी ने सूचित किया है कि औद्योगिक स्मार्ट सिटीज के विकास का उद्देश्य विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं के साथ बड़े पैमाने पर विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इन परियोजनाओं में विनिर्माण/प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा रोजगार पाने वालों के कौशल को उन्नत और विकसित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके। वर्तमान और भविष्य की जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, शहरी केंद्रों को जोड़ा जाएगा जिससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। जब ये परियोजनाएं शुरू होंगी, तब सामाजिक-आर्थिक आंतरिक रिटर्न दर (आईआरआर) इन परिणामों की पुष्टि करेगी। उद्योग में लगने वाली लॉजिस्टिक लागत और समय को अत्याधिक कम करके इसे लाभान्वित करने का उद्देश्य है क्योंकि ये केंद्र समर्पित रेलवे फ्रेट कॉरिडोर और / या अन्य प्रकार के परिवहन नेटवर्क के पास स्थित हैं, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, स्मार्ट सिटी में प्लॉट स्तर तक विश्वसनीय औद्योगिक अवसंरचना, निजी उद्यमियों द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए समय को कम करने के लिए 'प्लग एंड प्ले' अवसंरचना, सामान्य अवसंरचना जैसे कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपी) / वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स (डब्ल्यूटीपी) / सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) आदि के माध्यम से उद्योगों द्वारा प्रारंभिक

पूंजीगत व्यय का बोझ कम करना, व्यापार करने में आसानी और तालमेल एवं इकोनॉमी ऑफ स्केल के लिए मेगा-क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण में सुधार करना है।

(घ) एनआईसीडीपी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 28.08.2024 को 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटीज को अनुमोदित किया गया है, जिसमें इक्विटी/ऋण के रूप में भारत सरकार का योगदान (राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के माध्यम से) 12,366 करोड़ रु. है।

*****

अनुलग्नक

'औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना' के संबंध में 02.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 67* (7 वां स्थान) के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनआईसीडीपी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	निवेश के लिए क्षेत्र/सेक्टर
1	एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) खुरपिया	उत्तराखंड	औद्योगिक स्मार्ट सिटीज में निवेश के लिए जिन क्षेत्रों में निवेश प्रक्रिया परिभाषित की गई है, वे इस प्रकार हैं - भारी इंजीनियरिंग, ऑटो और सहायक उपकरण, सामान्य विनिर्माण, फार्मा और जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटीईएस), कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद, एयरोस्पेस, रबड़ और प्लास्टिक, फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), फैब्रिकेशन (सेमीकंडक्टर), नैनो टेक्नोलॉजी और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स आदि।
2	आईएमसी राजपुरा	पंजाब	
3	दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र	महाराष्ट्र	
4	पलक्कड़ औद्योगिक क्षेत्र	केरल	
5	जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र	राजस्थान	
6	आईएमसी आगरा	उत्तर प्रदेश	
7	आईएमसी प्रयागराज	उत्तर प्रदेश	
8	आईएमसी गया	बिहार	
9	आईएमसी हिसार	हरियाणा	
10	कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	
11	ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	
12	जहीराबाद	तेलंगाना	